Zero Hour Mentions, it is "Movement of Civil Disobedience in Protest against Price Rise." If the production is more, why is there price-rise? You are saying that there is no price-rise. ...*(Interruptions)*

Then it is okay.

SHRI M.A. BABY (Kerala): This is disobedience to facts.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is-not disobedience to facts. Disobedience is being adopted by him by bringing the disobedience movement.

Madam, apart from that, the hon. Member says that the Government could not check the price-line. As far as the question of inflation and price-rise is concerned, it was in double digit, and it has come down to 9.93 per cent. ...*(Interruptions)*

DR. BIPLAB DAS GUPTA: It is a temporary fluctuation. ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay Mr. Narayanasamy, one minute.

I have a solution, please. I have a solution. We are discussing the Appropriation Bills after we finish this. I would like them to express their very valuable views and points and to elaborate their views on the economic-scene at that time. Now that is over ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, only one sentence. Our exports have increased. Our foreign exchange reserve is more than $17 million. ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now that is over....*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, this is the problem with our communist friends. ...*(Interruptions)*

In West Bengal, they want the private sector to come. The public sector units arc being sold to the private sector. They are adopting our economic policy anil they are criticising us!

माननीय सदस्य श्री बिप्लब दासगुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं अपने को उनके साथ एसोसिएट करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो न्यू इकॉनोमिक पॉलिसी के चलते देश में मूल्य-वृद्धि हो रही है और इनवेस्टमेंट में कमी आ रही है, औद्योगिक विकास ठप्प पड़ रहा है, उसकी तरफ सरकार अविलम्ब ध्यान दे।

मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभापति जी, डा० विप्लव दासगुप्त ने जो विषय उठाया है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है; यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा अनुरोध है कि उनकी मांग को देखते हुए सरकार को जो अपनी आर्थिक नीति है, उसका पुनरीक्षण करना चाहिए क्योंकि आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि सरकार ने शायद यह भी फैसला लिया है कि हालैण्ड, नीदरलैंड से गोबर भी आयात किया जाएगा भारत में।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, I should announce the topic also so that the Members can confine themselves to the original Special Mention and Zero Hour mentions. The Special Mention is on Police firing at Sahebganj District in Bihar.

Re. Police Firing in Sahebganj District in Bihar

श्री जनार्दन यादव (बिहार): मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार, दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और बिहार में सबसे पिछड़ा संथाल परगना साहिबगंज। इसी साहिबगंज में 27 जुलाई को साहिबगंज की जनता साहिबगंज से लोकोशेड हटाकर मालदा ले जाने की तैयारी को रोकने के लिए इकट्ठा हुई, शांतिपूर्ण ढंग से लोकोशेड रोकने का काम कर रही थी, बिना प्रोवोकेशन के, बिना उत्तेजना के अपना काम कर रही थी। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें सात लोग मारे गए। दुर्भाग्य यह है कि सात दिन तक साहिबगंज में कर्फ्यू लगा रहा। एक लाश बरामद हुई, छह लाश बरामद नहीं हुई। आज भी दस आदमी पुलिस गोली से घायल हैं। वहां रेलवे विभाग का न तो कोई मंत्री और न ही अधिकारी पहुंचा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि साहिबगंज की पुलिस फायरिंग का जस्टीफिकेशन यहां हाउस में है। साथ ही मरने वालों और जो घायल है, उनके परिवार को दो दो लाख रुपया गुजर बसर के लिए दिया जाए।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): मैडम, जो घटना साहिबगंज में हुई है, उसी तरह की घटना बिहार में दूसरी जगह भी होने वाली है। चूंकि आज एम्पलायमेंट कहीं मिल नहीं रहा है और इस लोकोमेटिव से कुछ एम्पलायमेंट रेलवे की तरफ से दिया गया है। बिहार में एक दूसरी जगह है झाझा, वहां से भी लोकोमोटिव हटाया जा रहा है। लोग वहां रोजाना धरणा दे रहे है, घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से चाहूंगा कि इन बातों के ऊपर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें, नहीं तो जो घटना साहिबगंज में घटी है, वही घटना झाझा में घटने वाली है। सरकार चेतावनी से इस बात को सुन ले कि इस घटना को अगर रोकना है तो कोई शीघ्र निर्णय ले।

उपसभापति: श्री सत्य प्रकाश मालवीय।
...(व्यवधान)...

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): साहिबगंज की जो घटना है और झाझा के लिए जिस घटना की आशंका व्यक्त की है, इस भावना से हम रेल मंत्री जी को अवगत कराएंगे।
...(व्यवधान)...

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): आप अपनी भावना भी कह दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): यह क्या अवगत कराने की बात कही है? ...(व्यवधान)...

उपसभापति: उनका मंत्रालय नहीं है।
...(व्यवधान)...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: तो बाकी मेंशन जो यहां पर होते हैं, क्या उनके बारे में सूचना नहीं जाती?

श्री चतुरानन मिश्र: सूचना जाती है, लेकिन
...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर ठाकुर: रेल मंत्री का कर्तव्य है, लेकिन हम साहिबगंज डेलीगेशन के साथ रेल मंत्री से मिले हैं और उनके अधिकारीगण से भी, वहां की समस्या के समाधान के लिए। लेकिन, अभी जो जिक्र यहां हुआ है, उसका उल्लेख पुनः हम रेल मंत्री से करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: झाझा का भी।
...(व्यवधान)...

उपसभापति: चलिए, मालवीय जी, बोलिए। यू० पी० का बोलिए।

Re. Problems of Hilly Areas of U.P.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के आठ जिले हैं—नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी और देहरादून। वहां पर आरक्षण के संबंध में पिछले 2 अगस्त से बहुत आंदोलन हो रहा है और उसने कहीं कहीं पर हिंसा का रूप भी धारण कर लिया है, उग्र रूप धारण कर लिया है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं आंदोलनकारियों को, कि अहिंसा का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। वहां के उत्तराखंड क्रांति दल के नेता इन्द्रमणि बडोनी, जो उत्तर प्रदेश में विधायक भी रहे हैं, पिछले 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अपने पांच-छह साथियों के साथ पहले मेरठ मेडीकल कालेज में थे और परसों शाम उन्हें दो साथियों के साथ आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंस में लाया गया है। कल मैं इनसे मिलने के लिए भी गया था। इनकी अवस्था करीब करीब 75 वर्ष की है। हालत इनकी काफी गंभीर है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत ही हठवादिता का रुख अपनाया है। यहां तक मेरी जानकारी है और जो कुछ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मैदानी इलाकों के लोगों को भड़का दूं तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनको भागकर पहाड़ी क्षेत्रों में आना पड़ेगा। तो इस तरीके का वक्तव्य एक जिम्मेदार मुख्य मंत्री को नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि यह विषय ज्यादा गर्म न हो, ज्यादा इसमें हिंसा न फैलने पाए, इसलिए भारत सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और इन पहाड़ी क्षेत्रों के जितने भी विधायक है—विधान सभा, विधान परिषद के सदस्य है, उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के मैम्बर्स हैं राज्य सभा के और लोक सभा के और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, इनके अतिरिक्त और भी जो वहां के महत्वपूर्ण नेता है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाकर, उनकी मीटिंग बुलाकर इस समस्या का एक शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों ने इस देश को गोविन्द वल्लभ पंत दिया है, इस देश को हेमवती नन्दन बहुगुणा दिया है, इस देश को नारायण दत्त तिवारी दिया है, जो आज भी हमारे बीच में हैं और ये तीनों उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। चौथे श्री चन्द्रभान जी गुप्ता थे, जो मैदानी इलाके के थे, ये 'रानीखेत'' पहाड़ी